eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

आत्मनिर्भर भारत की चुनौतियाँ और मुद्दे

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]

[1]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ0प्र0, भारत

Received: 20 June 2023 Accepted: 28 June 2023, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2023

Abstract

आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India) की संकल्पना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त भूमिका निभाने के उद्देश्य से की गई है। इस शोध पत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान की पृष्ठभूमि, इसके लक्ष्य, चुनौतियाँ और इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अंतर्गत आर्थिक सुधार, औद्योगीकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचा और वैश्विक व्यापार से संबंधित पहलुओं की समीक्षा की गई है। साथ ही, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक रणनीतियों और नीतिगत सुधारों पर भी चर्चा की गई है।

कीवर्ड– आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक सुधार, औद्योगीकरण, कृषि विकास, तकनीकी नवाचार, वैश्विक व्यापार, स्टार्टअप, आत्मनिर्भरता।

Introduction

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें उत्पादन, नवाचार, तकनीकी प्रगति, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास शामिल है। यह पहल इस विचार पर आधारित है कि किसी भी देश की वास्तविक स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित होती है जब वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। भारत की विशाल जनसंख्या, विविध प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती युवा शक्ति इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने की क्षमता रखते हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, इसकी चुनौतियों और प्रमुख मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण करना है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलुओं को भी शामिल किया जाता है। भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार, अनुसंधान और औद्योगिक विकास को समान रूप से महत्व दिया जाए।

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा का मुख्य आधार यह है कि भारत को अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी संसाधनों और नवाचार का उपयोग करना चाहिए। यह

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

अभियान देश में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि विनिर्माण, कृषि, सेवा और प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम, जैसे कि 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' और 'उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना' (PLI) इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हालांकि, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की राह में कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें वित्तीय संसाधनों की कमी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आवश्यक तकनीकी और नवाचार में पिछड़ापन, प्रशासनिक जटिलताएँ और श्रम कौशल की कमी प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस शोध पत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए आवश्यक रणनीतियों और सुधारों पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पाँच मुख्य स्तंभों की पहचान की गई है– 1. ''अर्थव्यवस्था'' आर्थिक सुधार और सतत विकास की दिशा में कदम। 2. ''बुनियादी ढाँचा'' आधुनिक बुनियादी ढाँचे का विकास। 3. ''प्रौद्योगिकी और नवाचार'' डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप को बढ़ावा। 4. ''जनसांख्यिकी'' युवा शक्ति और मानव संसाधन का अधिकतम उपयोग। 5. ''मांग'' घरेलू उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आत्मनिर्भरता से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया है जो स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए वैश्विक स्तर पर भी सशक्त भूमिका निभा सके। आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसमें भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर न होकर, आंतरिक संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग कर आत्मनिर्भर बने। यह केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और नवाचार जैसी विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। आत्मनिर्भरता का विचार भारत में नया नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने 'स्वदेशी' और 'स्वावलंबन' का जो संदेश दिया था, वही आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव बना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को बढ़ावा मिला। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण आत्मनिर्भरता का पारंपरिक मॉडल बदला और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मेड इन चाइना' और तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकनीकी विकास और गुणवत्ता–निर्माण की नीति अपनाई, जिससे वह वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बन गया। सरकारी सहयोग और नवाचार के माध्यम से दक्षिण कोरिया ने अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाया और वैश्विक ब्रांड्स तैयार किए। जर्मनी ने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और कुशल कार्यबल पर ध्यान दिया, जिससे वह एक वैश्विक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

निर्यातक देश बन गया।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया है, अर्थव्यवस्था (Economy) एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन की बजाय एक बृहद बदलाव को अपनाए। बुनियादी ढाँचा (Infrastructure) आधुनिक भारत के निर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा। प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology & Innovation) आत्मनिर्भरता के लिए डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना। जनसांख्यिकी (Demography) भारत की युवा जनसंख्या को कुशल और सक्षम बनाना। मांग (Demand) घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित किया है। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, 'मेक इन इंडिया' और 'मेड इन इंडिया' पहल के तहत घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। रोजगार के अवसर सृजित करना, स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर व्यापक स्तर पर नौकरियाँ उपलब्ध कराना। नवाचार को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति सुनिश्चित करना। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त, भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र में नवाचार, जैविक खेती और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत करना। MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का विकास, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता एवं बाजार उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्यों को अपनाना।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारतरू भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। स्थानीय उत्पादों का समर्थन, 'वोकल फॉर लोकल' पहल के तहत स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया का विस्तारू ई–गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और आईटी उद्योग का सशक्तिकरण। वैश्विक व्यापार नीति, निर्यात को बढ़ाने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए रणनीतियाँ बनाना। वित्तीय समावेशन, बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना। कौशल विकास और शिक्षारू नई तकनीकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल विकास करना। MSME को प्रोत्साहन, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए आसान ऋण योजनाएँ लागू करना।

आत्मनिर्भर भारत से संभावित लाभ

आर्थिक स्थिरता, भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी प्रभावों से सुरक्षित होगी। रोजगार वृद्धि, नए उद्योग और स्टार्टअप अधिक रोजगार उत्पन्न करेंगे। वैश्विक नेतृत्व, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकेगा।

तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और विकास में बढ़ोत्तरी होगी। स्थायी विकास, पर्यावरण–संवेदनशील नीतियों को अपनाया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य है कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

भूमिका निभाए। इसके लिए निवेश, औद्योगिकीकरण, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इनमें कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं–

आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता और सुधार उपाय शामिल थे। पीएलआई (Production&Linked Incentive) योजना, विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन–लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना लागू की, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से इन योजनाओं को सशक्त किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड–19 महामारी के दौरान गरीबों और वंचित वर्गों को राहत देने के लिए इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न और आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, इस पहल से प्रवासी श्रमिकों और गरीब वर्ग के लोगों को देशभर में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मिली। कृषि सुधार कानून, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सुधारों को लागू किया गया। विनिर्माण क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय उद्योगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है।

रक्षा क्षेत्र, मेक इन इंडिया, पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है और कई रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्वास्थ्य और फार्मा उद्योग, कोविड–19 महामारी के दौरान भारत ने बड़ी मात्रा में टीकों और दवाओं का उत्पादन किया और अन्य देशों को निर्यात किया। खाद्य और कृषि, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। यूपीआई (UPI) और डिजिटल भुगतान, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को विश्व स्तर पर सराहा गया है और इससे अर्थव्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया गया है। 5G और इंटरनेट विकास– भारत 5G तकनीक के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं में सुधार होगा।

मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, भारत में घरेलू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर निर्माण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिला है। निर्यात में वृद्धि, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने निर्यात को बढ़ाया है, विशेष रूप से आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल में। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी, भारत अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है, जिससे घरेलू विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

सक्रिय भागीदारी, भारत ने विभिन्न व्यापारिक समझौतों के तहत अपनी भागीदारी को मजबूत किया है, जिससे व्यापार संतुलन को बनाए रखने में मदद मिली है। हालांकि, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बढ़ती बेरोजगारी, छोटे और मध्यम उद्यमों (डैडम्) को अधिक समर्थन की आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचा, उद्योगों की वृद्धि के लिए आधुनिक लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना आवश्यक है।

तकनीकी और अनुसंधान में निवेश, अनुसंधान और विकास (R&D) में अधिक निवेश की आवश्यकता है ताकि भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बन सके। नीतिगत सुधारों का धीमा कार्यान्वयनरू कई सुधार लागू तो किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धारू भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए निरंतर सुधार करने होंगे।

हरित ऊर्जा और पर्यावरण, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। वैश्विक विनिर्माण हब, भारत अपने उद्योगों और स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाकर वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिक कृषि तकनीकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाना आवश्यक है।

बेरोजगारी और रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना आवश्यक है। हालांकि, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को वित्तीय सहयोग MSME सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन पूँजी की कमी, क्रेडिट गारंटी की समस्याएँ और बाजार तक सीमित पहुँच इस क्षेत्र के विकास में बाधा बन रही है।

वैश्विक निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बावजूद, भारत को विदेशी निवेश की आवश्यकता है। लेकिन जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएँ और विनियामक बाधाएँ निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं। बैंकिंग और वित्तीय ढाँचे की चुनौतियाँ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या बनी हुई है, जिससे वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ता है।

विनिर्माण क्षेत्र का सीमित विकास, मेक इन इंडिया, अभियान के बावजूद, उत्पादन लागत, तकनीकी पिछड़ापन और नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण भारत में उद्योग तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रणाली, उच्च लॉजिस्टिक लागत और परिवहन सुविधाओं की कमी से व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संकटरू स्थायी और किफायती ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में।

स्वदेशी अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश की कमी, भारत में अनुसंधान और नवाचार पर GDP का अपेक्षाकृत कम हिस्सा खर्च किया जाता है, जिससे नवीन तकनीकों और उत्पादों का विकास सीमित रहता

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

है। उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बावजूद, भारत को अर्धचालक (semiconductor), मशीनरी और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

डिजिटल अवसंरचना और साइबर सुरक्षा, भारत में डिजिटल क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। शिक्षा और कौशल विकास, आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी असमानता, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता और डिजिटल डिवाइड आत्मनिर्भरता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। महिला सशक्तिकरण और कार्यबल भागीदारी, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी कम होने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। नीतिगत अस्थिरता और नौकरशाही बाधाएँ, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक स्थिर और व्यापार–अनुकूल नीति वातावरण आवश्यक है। कानूनी और नियामक ढाँचे की जटिलता, भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएँ और कर प्रणाली अभी भी जटिल बनी हुई हैं। नीतियों का धीमा कार्यान्वयन, योजनाएँ और सुधार घोषित किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी कार्यान्वयन धीमा होता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो पहले से ही वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति रखते हैं। आयात निर्भरता, आत्मनिर्भर बनने के बावजूद भारत को अभी भी कई महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे उन्नत मशीनरी, कच्चे माल और उन्नत तकनीकों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ, विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध और संरक्षणवादी नीतियाँ भारतीय व्यापार के विकास में बाधा बन सकती हैं। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देनारू भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार की मेक इन इंडिया और श्प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत को उच्च तकनीकी उत्पादों के निर्माण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत रणनीति अपनानी होगी। बड़े उद्योगों और MSME सेक्टर का समन्वय, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है ताकि वे मिलकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान दे सकें।

कृषि में नवाचार, परंपरागत कृषि पद्धतियों के बजाय आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती और स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाना आवश्यक है। किसानों की आय बढ़ाना, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बाजार तक पहुँच, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन और निर्यात को बढ़ावा देना आवश्यक है। भंडारण और वितरण प्रणालीरू भारतीय कृषि क्षेत्र में उपज की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। खाद्य भंडारण और लॉजिस्टिक्स में निवेश आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास, आत्मनिर्भर भारत के तहत सौर, पवन और जलविद्युत ऊर्जा पर जोर देना आवश्यक है। पर्यावरणीय चुनौतियाँ, औद्योगिकीकरण के साथ–साथ सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। ईंधन आयात पर

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

निर्भरता, भारत अभी भी तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर है, जिसे कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा।

डिजिटल भारत अभियान का विस्तार, आत्मनिर्भरता के लिए डिजिटल अवसंरचना को और अधिक विकसित करना आवश्यक है। साइबर सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना आवश्यक है ताकि डिजिटल इंडिया की सफलता सुनिश्चित हो सके। स्वदेशी चिप निर्माणरू अर्धचालक (semiconductor) उद्योग को विकसित करना महत्वपूर्ण है ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उत्पादों के लिए आत्मनिर्भर बन सके। स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मनिर्भरता, देश में चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मनिर्भर भारत के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। रिसर्च और इनोवेशन, उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि भारत उन्नत अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। निर्यात क्षमता का विस्तार, वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ बनानी होंगी। आर्थिक कूटनीति, व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है। भारतीय ब्रांड्स का वैश्विक स्तर पर विस्तार, भारतीय ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और व्यापार सुविधाओं को बेहतर बनाना आवश्यक है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। उत्पादन लागत, कौशल विकास, और बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता। 'मेक इन इंडिया' और 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)' योजना का प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। स्थानीय निर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कर रियायतें और सरकारी समर्थन। नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन। विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश। घरेलू कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा देना ताकि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हो। एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लाखों नौकरियाँ प्रदान करता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग। निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए वैश्विक बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना। डिजिटल प्लेटफार्म और ई–कॉमर्स के माध्यम से डैडम उत्पादों की मार्केटिंग। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार। विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक गलियारों (Industrial Corridors) का विकास। घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। आयात निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ और नीतिगत सुधार।

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है और देश के जीडीपी का लगभग 55ः हिस्सा बनाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन और मनोरंजन जैसे उद्योग शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत सेवा क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनाने के प्रयास। भारत आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी है। डिजिटल

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाएँ आईटी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही हैं। डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन और बिग डेटा एनालिटिक्स का बढ़ता उपयोग। आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) आवश्यक है। डिजिटल भुगतान प्रणाली और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का विस्तार। बैंकिंग क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक बैंकों की भूमिका। फिनटेक स्टार्टअप्स और माइक्रोफाइनेंस का विकास।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं का उत्पादन। मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी और टेलीमेडिसिन में नवाचार। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'देखो अपना देश' और 'स्वदेश दर्शन' जैसी योजनाएँ। वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढाँचे में सुधार। सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन। स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उद्योगों को पर्यटन से जोड़ने के प्रयास।

स्टार्टअप इंडिया योजना और उसके तहत नवाचार को बढ़ावा। नए बिजनेस मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विकास। फंडिंग, वेंचर कैपिटल और एंजेल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के उपाय। महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना। आउटसोर्सिंग उद्योग में सुधार और विदेशी कंपनियों के लिए भारत को आकर्षक बनाना। वैश्विक मानकों के अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में भारत की सेवा–आधारित रणनीतियाँ। डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय बढ़ाना। आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा। स्वदेशी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार। युवाओं और महिलाओं को उद्यमशीलता और नवाचार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार, उद्योग, नागरिक और शिक्षाविदों के बीच एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। यह केवल आर्थिक पहल नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की एक रणनीतिक योजना है। सही नीतियों, निवेश और नागरिक सहभागिता से, भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सकता है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है।

भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और उसकी वैश्विक व्यापार में भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे G20, WTO और BRICS में भारत की भूमिका को मजबूत बनाना।

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूर्णतः आत्मनिर्भर होना नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

मजबूत भागीदार बनना है। युवाओं को सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा नवाचारों के माध्यम से नए समाधान विकसित कर रहे हैं। महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा देकर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। उचित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्टार्टअप और उद्यमशीलता के माध्यम से भारत के युवा देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन दिया जा रहा है। यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण भी इसका एक प्रमुख पहलू है। महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और अन्य कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ लागू की जा रही हैं। ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और स्थानीय कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल पहल के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय विरासत की रक्षा के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की जा रही हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली, योग, आयुर्वेद और पारंपरिक विज्ञान को मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जा रहा है।

सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह (HG) और अन्य संगठनों के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को सशक्त किया जा रहा है। समाज में सामूहिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नागरिकों को विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है।

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड–19 महामारी के दौरान स्वदेशी दवाओं और स्वास्थ्य प्रणालियों की उपयोगिता बढ़ी है। भारत को स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, जैविक खेती और सतत शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अन्य सरकारी पहलें आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी एक समग्र परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में किए गए प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत केवल आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र भी बने।

आर्थिक सुधारों के तहत व्यापार को आसान बनाने, नौकरशाही की बाधाओं को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को दीर्घकालिक नीतिगत सुधारों पर ध्यान देना होगा। डिजिटल प्रशासन, ई–गवर्नेंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग से प्रशासनिक दक्षता में सुधार किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन और निवेश को बढ़ावा, लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) को वित्तीय सहायता और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिक उद्यमिता अनुदान और निवेश योजनाएँ लागू करनी होंगी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर भारत को वैश्विक निवेश केंद्र बनाना होगा।

आत्मनिर्भर भारत के तहत नई तकनीकों जैसे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (और स्वचालन (Automation) को बढ़ावा देना आवश्यक है। अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश को बढ़ाकर भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना होगा। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को ध्यान में रखना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर देना होगा। भारत को ग्रीन इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए सतत कृषि और हरित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।

आत्मनिर्भर भारत के लिए नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डिजिटल साक्षरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। युवाओं के लिए उद्योग–केंद्रित प्रशिक्षण और अपस्किलिंग (Upskilling) प्रोग्राम्स को लागू करना आवश्यक है।

कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैविक खेती, स्मार्ट खेती और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना होगा। किसानों को नई तकनीकों और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए अधिक डिजिटल समाधान विकसित करने होंगे। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतियाँ अपनानी होंगी।

मेड इन इंडिया उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए गुणवत्ता सुधार और ब्रांडिंग पर ध्यान देना होगा। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढाँचे में निवेश करना होगा। विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को रणनीतिक रूप से लागू करना आवश्यक है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए अनुसंधान और उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करना होगा। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा) को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए प्रयास करने होंगे।

महिलाओं, ग्रामीण समुदायों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आत्मनिर्भर भारत में समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। वित्तीय समावेशन के लिए अधिक बैंकिंग सुविधाएँ और डिजिटल भुगतान तंत्र विकसित करने होंगे। सामाजिक कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डेटा–संचालित रणनीतियाँ अपनानी होंगी।

आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अभियान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुधारों, निवेश, नवाचार, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतियाँ अपनानी होंगी। यदि इन रणनीतियों को समुचित रूप से लागू किया जाए, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा सकता है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अभियान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुधारों, निवेश, नवाचार, शिक्षा और सतत विकास के क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतियाँ अपनानी होंगी। यदि इन रणनीतियों को समुचित रूप से लागू किया जाए, तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य केवल उत्पादन और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी और स्थायी विकास की अवधारणा है। इसमें सभी क्षेत्रों का योगदान आवश्यक है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, सेवा क्षेत्र हो या फिर शिक्षा और अनुसंधान। जब हर भारतीय इस विचार को अपनाएगा और इसके लिए कार्य करेगा, तभी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी।

संदर्भ सूची–

1- भारत सरकार, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आधिकारिक वेबसाइट, 2020।

2- नीति आयोग, आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतियाँ, 2021।

3- भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, वार्षिक रिपोर्ट, 2022।

4- डॉ. अरविंद पानगड़िया, भारतीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021।

5- विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएँ जैसे कि द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, और बीबीसी हिंदी।

6- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), भारत में सतत विकास, 2022।

7- वर्ल्ड बैंक, भारत की आर्थिक नीति और आत्मनिर्भरता, 2021।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 06, Issue 02, July 2023

8- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), भारत की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, 2020।

9- सीआईआई (CII), भारतीय उद्योग और आत्मनिर्भरता, 2021।

10- फिक्की (FICCI), स्टार्टअप इंडिया और उद्यमशीलता, 2022।

11- एसोचौम (ASSOCHAM), भारत में औद्योगिक विकास, 2021।

12- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI), आत्मनिर्भर भारत पर रिपोर्ट, 2020।

13- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारत की वैद्विवक प्रतिस्पर्धा, 2022।

14- नीति आयोग, भारतीय कृषि और आत्मनिर्भरता, 2021।

15- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय तकनीकी नवाचार, 2021।

16- ग्रामीण विकास मंत्रालय, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास, 2020।

17- एमएसएमई मंत्रालय, लघु एवं मध्यम उद्योग और आत्मनिर्भरता, 2022।

18- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR), भारतीय नीतिगत सुधार, 2021।

19- टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS), भारतीय समाज और आत्मनिर्भरता, 2020।

20- IIM अहमदाबाद, व्यापार और अर्थशास्त्र में आत्मनिर्भरता, 2021।

21- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ष्आर्थिक आंकड़े और विकास, 2022।

22- यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, भारतीय नीतियाँ और अर्थव्यवस्था, 2021।

23- सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSD), भारत में सामाजिक सुधार, 2020।

24- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता, 2021।

25- मैकिन्से इंडिया, भारतीय बाजार और आर्थिक सुधार, 2022।